सोना-चांदी का सफर

निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न

एक महीने के भीतर चांदी ने जो तेजी दिखाई उससे लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न मिला

नई दिल्ली, 20 जनवरी. भारत में सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं, बल्कि परंपरा, सुरक्षा और निवेश का भरोसेमंद साधन माने जाते रहे हैं. बीते कई दशकों में इनकी कीमतों ने लंबा और उतार-चढ़ाव भरा सफर तय किया है.

महंगाई, आर्थिक संकट, युद्ध, वैश्विक मंदी और राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर में जब-जब दूसरे निवेश विकल्प डगमगाए, तब-तब सोना और चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में उभरे. आज जब 24 कैरेट सोना रुपए 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है, तब यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर इसकी कीमत यहां तक

कैसे पहुंची. आजादी के समय जहां 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ रुपए 88 थी, वहीं 1990 के दशक में यह रुपए 3,200 के स्तर को पार कर चुकी थी. चांदी ने एक बार फिर निवेशकों को चौंकाते हुए नया इतिहास रच दिया है. 19 जनवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के दाम 3.02 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए. महज एक महीने के भीतर चांदी ने जो तेजी दिखाई है, उसने न सिर्फ निवेशकों का ध्यान खींचा है, बल्कि बाजार के पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. इसी तरह चांदी, जिसे कभी गरीब आदमी का सोना कहा जाता था, ने भी लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न दिया है.

> वैश्विक स्तर पर 2008 के वित्तीय संकट के दौरान चांदी की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. संकट से पहले यह लगभग 20 डॉलर प्रति औंस थी, लेकिन घबराहट में हुई बिकवाली के चलते यह गिरकर करीब 9 डॉलर तक आ गई. इसके बाद 2010 और 2011 में चांदी ने जबरदस्त वापसी की और 2011 की पहली तिमाही में इसकी औसत कीमत 31.86 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई.

आर्थिक इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि सोना-चांदी की कीमतों में आई तेजी केवल मांग का नतीजा नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक हालात, मुद्रा संकट और निवेशकों की मानसिकता का भी प्रतिबिंब रही है.

रुपया 11 पैसे टूटा, दूसरे निचले स्तर पर

मुंबई, 20 जनवरी. रुपया सोमवार को 11.25 पैसे टूटकर अब तक के दूसरे निचले स्तर पर आ गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.90 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा में यह लगातार चौथी गिरावट है. पिछले कारोबारी दिवस पर यह 44.75 पैसे लुढ़ककर 90.7875 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. चार दिन में यह 72.50 पैसे टूटी है. रुपये का ऐतिहासिक निचला स्तर 16 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया था जब यह बीच कारोबार में 91.14 रुपये प्रति डॉलर तक लुढ़कने के बाद 90.93 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. रुपये में सुबह के कारोबार में तेजी रही. यह 10.75 पैसे मजबूत होकर 90.68 रुपये प्रति डॉलर पर खुला. यह ऊपर 90.65 रुपये प्रति डॉलर तक चढ़ने के बाद लुढ़कता हुआ 91.01 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया.

टैक्स सुधार सरकार की प्राथमिकता

बजट 2026 से पहले सामने आया रिपोर्ट कार्ड : निर्मला सीतारमण

1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने की तैयारी

नई दिल्ली, 20 जनवरी. केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश करने से पहले सरकार ने अपनी तैयारियों का संकेत देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक तरह का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए पिछले बजट में किए गए अहम ऐलानों और उन पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी साझा की.

टैक्स सुधार, निवेश को बढ़ावा और कर प्रणाली को सरल बनाने जैसे मुद्दे इस रिपोर्ट के केंद्र में रहे. सरकार का साफ संदेश है कि आने वाले बजट से पहले टैक्सपेयर्स और निवेशकों को

भरोसा दिलाया जाए कि घोषित नीतियों को जमीन पर उतारा जा रहा है. न्यू टैक्स रिजीम में किए गए बदलावों से लेकर कॉरपोरेट टैक्स में दी गई रियायतों तक, वित्त मंत्रालय ने यह बताने की कोशिश की है कि कर सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं. ऐसे समय में जब आम करदाता महंगाई और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा है, टैक्स देने के बाद हाथ में ज्यादा पैसा बचाने की नीति को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है.

> केंद्र सरकार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने की तैयारी कर रही है. बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को पिछले बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं और उन पर अब तक हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा साझा किया. इस रिपोर्ट कार्ड में टैक्स सुधारों को सबसे अहम उपलब्धि के रूप में रखा गया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत न्यू टैक्स रिजीम में व्यक्तिगत आयकर ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं. इन सुधारों का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और टैक्स चुकाने के बाद आम लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम छोड़ना है. मंत्रालय ने बताया कि ये सभी बदलाव वित्त वर्ष 2025-26 से लागू हो चुके हैं और इनका असर आकलन वर्ष 2026-27 से करदाताओं को दिखाई देगा.

दावोस से महाराष्ट्र को निवेश की बंपर सौगात

दावोस/मुंबई, 20 जनवरी. स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से महाराष्ट्र के लिए निवेश की बड़ी सौगात सामने आई है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने देश और विदेश की कई नामी कंपनियों तथा वैश्विक संस्थानों के साथ हजारों करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों से राज्य में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. सरकार के अनुसार, दावोस में हुए ये करार महाराष्ट्र को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और

मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं. रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में मजबूती मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात कर महाराष्ट्र की निवेश-अनुकूल नीतियों और संभावनाओं को रेखांकित किया. विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कई अहम निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें राज्य के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुए इन करारों में रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है.

उपेक्षित इलाकों में ऋण दें यूसीबी

मुंबई, 20 जनवरी. केंद्रीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से उपेक्षित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की अपील की है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यहां चुनिंदा यूसीबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि उपेक्षित इलाकों में ऋण देने में और वित्तीय समावेशन बढ़ाने में यूसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने पिछली बैठक के बाद से सहकारी बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की पहलों के बारे में भी जानकारी दी. श्री मल्होत्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों के परिणामस्वरूप यह सेक्टर मजबूत बनेगा और इसका स्वस्थ विकास होगा.

टैरिफ विवाद बढ़ा, भारतीय शेयर बाजार लुढ़का

नई दिल्ली, 20 जनवरी. वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ तनाव का सीधा असर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला. अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक शुल्क को लेकर बढ़ते गतिरोध ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

कमजोर ग्लोबल संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली ने घरेलू बाजार की धारणा को और कमजोर कर दिया. कारोबारी सत्र की शुरुआत से ही सेंसेक्स और निफ्टी पर बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे निवेशक सतर्क नजर आए. बाजार की यह कमजोरी ऐसे समय पर आई है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही भू-राजनीतिक तनाव, ऊंची ब्याज दरों और धीमी ग्रोथ जैसी चुनौतियों से जूझ रही है. अमेरिका द्वारा यूरोप के खिलाफ नए टैरिफ खतरों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है. इसका असर एशिया-प्रशांत बाजारों पर भी पड़ा, जहां ज्यादातर प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे.

हालांकि, इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की एफवाई -26 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया जाना एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. इसके बावजूद, अल्पकालिक तौर पर बाजार की दिशा वैश्विक घटनाक्रम और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर निर्भर करती नजर आ रही है.

> मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट देखने को मिली. सुबह करीब 9ः30 बजे, बीएसई सेंसेक्स 275 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,971 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 91 अंक या 0.36 प्रतिशत फिसलकर 25,494 के स्तर पर आ गया. कमजोर वैश्विक संकेतों और अमेरिका-यूरोप के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित किया. ब्रॉडकैप इंडेक्स भी बेंचमार्क के अनुरूप ही चले. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.33 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टोरल फ्रंट पर देखें तो निफ्टी एफएमसीजि, मेटल और पीयूएसयू बैंक को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे.पीयूएसयू बैंक इंडेक्स 1.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, जबकि रियल्टी और आईटी सेक्टर में क्रमशः 1.18 प्रतिशत और 0.65 प्रतिशत की गिरावट आई.

दस फरवरी के बाद भी नहीं रद्द होगी उड़ान

नई दिल्ली, 20 जनवरी. चालक दल के सदस्यों की तैनाती में 'कुप्रबंधन' के कारण पिछले साल दिसंबर के पहले सप्ताह में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करने वाली निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने नागर विमानन महानिदेशालय को बताया है कि उसके पास 10 फरवरी तक पर्याप्त संख्या में पायलट उपलब्ध होंगे और 10 फरवरी के बाद उड़ानें रद्द नहीं होंगी. डीजीसीए में पिछली साप्ताहिक बैठक के दौरान इंडिगो ने सोमवार को बताया कि उड़ानों की मौजूदा मंजूर संख्या के लिए डीजीसीए की फ्लाइट ड्यूटी से संबंधित छूट हटा लेने के बावजूद 10 फरवरी को पायलट की उपलब्धता को देखते हुए उड़ानें रद्द नहीं होंगी. उसने बताया कि 10 फरवरी को उसके पास एयरबस के 2,400 कमांड पायलट होंगे.

पीएम सेतु कार्यक्रम पर चर्चा में 40 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग

पुणे. देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए स्थापित संस्थानों और आईआईटी को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित पीएम-सेतु योजना को लागू करने के बारे में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में पुणे में उद्योग जगत के साथ आयोजित परामर्श कार्यक्रम में 40 से विभिन्न क्षेत्रों की अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया. मंत्रालय की ओर से सजारी विज्ञप्ति के अनुसार इस परामर्श में महिंद्रा एंड महिंदा, टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज और फिएट जैसी प्रमुख औद्योगिक कंपनियों और समूहों सहित वाहन, निर्माण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस, और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 40 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया. इस दौरान हब-एंड-स्पोक -धुरी और परिधि आईटीआई मॉडल, विशेष प्रयोजन इकाईयों के माध्यम से उद्योगों के नेतृत्व वाले संचालन, पाठ्यक्रम नवाचार, प्रशिक्षकों का उन्नयन रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने के विषयों पर चर्चा की गयी.

विंग्स इंडिया में एयरबस तलाशेगी संभावित पदों के लिए उम्मीदवार

नई दिल्ली, 20 जनवरी. फ्रांस की विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस विंग्स इंडिया 2026 में अपने विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन करने के साथ संभावित तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की तलाश भी करेगी. कंपनी ने बताया कि, वह 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित देश के प्रमुख एयरशो में एक इमर्सिव हेलीकॉप्टर सिम्युलेटर और अपनी एयरोस्पेस सेवाओं का पूरा पोर्टफोलियो प्रस्तुत करेगी.

समुद्री निर्यात पर भारत की वैश्विक पहल

नई दिल्ली, 20 जनवरी. भारत अपने समुद्री निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक और व्यावसायिक प्रयास तेज कर रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय मत्स्य विभाग 21 जनवरी को एक महत्वपूर्ण राउंडटेबल बैठक का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें 83 से अधिक देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भाग लेंगे.

83 देशों के राजदूतों के साथ राउंडटेबल

निवेश और बाजार पहुंच पर जोर

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब भारत समुद्री खाद्य निर्यात के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है और अब बाजार विस्तार, निवेश तथा मूल्यवर्धन पर जोर दे रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात

में वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है. वर्ष 2024-25 में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात 16.98 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिसका कुल मूल्य 62,408 करोड़ रुपये रहा. यह भारत के कुल कृषि निर्यात का करीब 18 प्रतिशत है. सरकार का मानना है कि बहुपक्षीय संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए इस क्षेत्र में और तेजी लाई जा सकती है.

टाटा मोटर्स ने पोर्टफोलियो को किया अपग्रेड

नई दिल्ली, 20 जनवरी. देश की अग्रणी वाणिज्यिक वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने पूरे ट्रक पोर्टफोलियो को अपग्रेड करते हुए मंगलवार को 17 नये ट्रक लॉन्च किये जिनमें पांच इलेक्ट्रिक ट्रक भी शामिल हैं.

टाटा मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक गिरीश वॉग और उपाध्यक्ष तथा ट्रक कारोबार के प्रमुख राजेश कौल ने यहां भारत मंडपम् में इन ट्रकों की लॉन्चिंग की. सिग्ना, प्राइमा, अल्ट्रा और ऑल न्यू अजूरा रेंज को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया है. ये ट्रक पहले के मुकाबले 1.8 टन तक ज्यादा भार ढोने की क्षमता रखते हैं और कंपनी का दावा है कि सात प्रतिशत तक कम ईंधन खपत के साथ अलग-अलग इस्तेमाल में ये 30 प्रतिशत तक ज्यादा मुनाफा देने में सक्षम हैं.

51 का लक्ष्य, 25 पर अटकी भाजपा

अमरावती. अमरावती मनपा चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित होते ही शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हालांकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अब चुनाव के बाद की राजनीति और महापौर पद को लेकर गुप्त लॉबिंग और रणनीतियों का खेल शुरू हो गया है.

महापौर पद के आरक्षण की घोषणा के साथ ही इसके लिए जमकर लॉबिंग चल रही है. चुनाव परिणाम के बाद नगरसेवक अपने-अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं. खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के चुने हुए नगरसेवकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि वे किसके साथ जाएंगे और किसे साथ लेंगे.

इस बीच भाजपा ने 51 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए 68 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. हालांकि भाजपा को महज 25 सीटें ही मिल पाईं, फिर भी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सत्ता की राह में अग्रणी होने का दावा किया है. सभी दलों को झटका भाजपा के अलावा सभी दलों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. इनमें कांग्रेस ने 74 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इसके अलावा युवा स्वाभिमान ने 33, शिंदे गुट ने 72, राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट ने 85, उबाठा ने 41, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ने 19, और एमआईएम, बसपा, वंचित, समाजवादी पार्टी ने भी जोरदार तैयारी की थी.

मणिपुर में सरकार बनाने की शर्त

इंफाल. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के एक साल पूरे होने जा रहे हैं. अगले महीने एक साल हो जाएगा. लेकिन अभी तक भाजपा लोकप्रिय सरकार के गठन का फैसला नहीं कर पाई है.

अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. तभी सवाल है कि क्या राज्य में सरकार का गठन होगा या राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार यह सुनने को मिला की कुकी समुदाय भी सरकार गठन के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने इसके लिए शर्त लगा दी है. कुकी समुदाय की शर्त है कि मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए.

प्रतीक ने निभाया, अपर्णा ने तोड़ा!

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत राजनेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई एक पोस्ट ने सूबे में हड़कंप मचा दिया. पोस्ट में कहा गया कि उनकी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने जिंदगी तबाह कर दी है. इस पोस्ट में अपर्णा को स्वार्थी महिला बताते हुए तलाक देने की बात भी कही गई. इस पोस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपर्णा यादव ने 19 जनवरी 2022 को बीजेपी की सदस्यता ली थी. पोस्ट की तारीख भी 19 जनवरी है. अब इसे महज संयोग कहेंगे या फिर सोचा.समझा कदम कहा जाए. क्योंकि अपर्णा के भाजपा ज्वाइन करने के ठीक तीन साल बाद 19 जनवरी को ही प्रतीक यादव ने अपर्णा से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया है.

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा एचएलसी-2 (सार्क विंग)
एचएलसी-2, चिनार इनक्यूब, होशंगाबाद रोड, आशिमा मॉल के सामने, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2983017

वित्तीय आस्तियों की वसूली अधिनियम SARFAESI Act. 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें यह सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

बकायादार/जमानतदार का नाम	सूचना दिनांक	देय राशि रु.	बंधक संपत्ति का विवरण एवं भवन/प्लाट की सीमाएं/ स्थिति
1. श्री पंकज मल्होत्रा पुत्र श्री ओ.पी. मल्होत्रा, 2. श्री पंकज मल्होत्रा स्व.श्रीमती उमा मल्होत्रा के कानूनी उत्तराधिकारी पता:-फ्लैट नं. बी-1, गोयल प्राइम अपार्टमेंट, सी26, बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा, जिला भोपाल, म.प्र.	NPA की दिनांक 19.01.2026 30.07.2025	खाता क्र.: 53000342225 दिनांक 19.01.2026 को रु. 2,40,691.00 + देय ब्याज व अन्य खर्च	आवासीय फ्लैट नं. बी1, गोयल प्राइम अपार्टमेंट, सी-26, बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित, **क्षेत्रफल :** 484.91 वर्ग फिट, **सीमाएँ-** पूर्व - प्लॉट नं. 25, पश्चिम - पार्किंग, उत्तर - फ्लैट नं बी-2, दक्षिण - रोड। **संपत्ति मालिक:** श्री पंकज मल्होत्रा पुत्र श्री ओ.पी. मल्होत्रा और श्रीमती उमा मल्होत्रा पत्नी पंकज मल्होत्रा।

नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ताओं और उनके गारंटर को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

इस बावत, ऋणी/जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (Redeem करने) के संबंध में अधिनियम की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 21.01.2026, स्थान : भोपाल **प्राधिकृत अधिकारी**

इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम-नवरत्न)
पश्चिम क्षेत्र, तल और तीसरी मंजिल, फोर्बस बिल्डिंग, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
IRCTC

वॉक-इन इंटरव्यू

होटल मॅनेजमेंट/हॉस्पिटॅलिटी प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटंट (CA)/कॉस्ट और मॅनेजमेंट अकाउंटंट (CMA)

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC), वेस्ट जोन **'कॉन्ट्रेक्ट बेसिस' पर 'हॉस्पिटॅलिटी मॉनिटर्स' और 'क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटंट (CA)/कॉस्ट और मॅनेजमेंट अकाउंटंट (CMA)'** की सेवाएं लेना चाहता है।

योग्यता मानदंड, वॉक-इन इंटरव्यू की तारीखों/स्थान और नौकरी की अन्य शर्तों के लिए कृपया देखें **https://www.irctc.com**

UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH
ADMISSION NOTICE (2026-2027)

Applications are invited for Admission to Two Year Full Time Management Programmes MBA, MBA (IB), MBA (HR), MBA (EP) and MBA (Business Data Analytics) for Academic Session 2026-27.

Candidates are required to visit the website https://ubsadmissions.puchd.ac.in for detailed instructions. The said website would remain open for online registration through online payment from 26.11.2025 to 28.01.2026. Hard copy of the application form along with necessary documents should reach the undersigned latest by 04:00 p.m. on 10.02.2026. Application received after due date shall not be entertained.

Note: Our Institution uses the CAT scores for short-listing/selecting the candidates for our Post-graduate Programme(s) in Management/ MBA. IIMs have no role either in the selection process or in the conduct of the programme.

Professor Parmjit Kaur, Chairperson

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा होम लोन सेन्टर-2 (सार्क विंग)
एचएलसी-2, भूतल, चिनार इनक्यूब, होशंगाबाद रोड, आशिमा मॉल के सामने, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2983018

आधिपत्य नोटिस (स्थावर सम्पत्ति) [13(4)]

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एवं धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित ऋणी एवं जमानतदारों को मांग सूचना निम्नलिखित दिनांक के अनुसार जारी किया। इस नोटिस की पावती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने केलिये कहा गया था।

ऋणी/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी/जमानतदारों को और आम जनता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट धारा 13(4) सहपठित उक्त कथित नियम (8) के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित सम्पति को उनके सामने दर्शाये गये दिनांक को कब्जे में लिया है। ऋणी/जमानतदारों को विशेष रूप से आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत् किए गये कोई भी व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक, शाखा एचएलसी-2, होशंगाबाद रोड, भोपाल** को देय ब्याज एवं खर्चो के अध्यधीन प्रभार (Charge) होगा। इस बावत, ऋणी/जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (Redeem करने) के संबंध में अधिनियम की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

बकायादार का नाम	60 दिवस मांग सूचना दिनांक	नोटिस राशि राशि रु.	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं भवन/प्लॉट की सीमाएँ/स्थिति
1) श्री अरुण कुमार द्विवेदी पुत्र श्री विष्णु प्रसाद द्विवेदी पता:- फ्लैट नं. बी04/303, ब्लॉक बी-04, तृतीय तल, फॉर्च्यून सौम्या अटलांटिस, ग्राम बागली, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)	27/11/2025 कब्जा दिनांक 19/01/2026	1) HL- 35974108316 Rs. 3,70,429.00 + देय ब्याज व अन्य खर्च	मकान नं. - फ्लैट नं. बी04/303, ब्लॉक बी-04, तृतीय तल फॉर्च्यून सौम्या अटलांटिस, ग्राम-बागली, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), क्षेत्रफल: 610.95 वर्ग फुट, सीमाएँ: पूर्व-कॉमन एरिया, पश्चिम - फ्लैट बी-05/302, उत्तर - फ्लैट बी-04/304, दक्षिण - रोड, श्री अरुण कुमार द्विवेदी पुत्र श्री विष्णु प्रसाद द्विवेदी के नाम पर।

दिनांक : 21.01.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

Email: cis.dgsystems@gov.in वेबसाइट : www.cbic.gov.in
Tender Id.: 2025_DREV_889258_1 तिथि: 21.01.2026

सूचना

सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) के लिए कार्यान्वियन एजेंसी (आईए) के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आरईओआई दस्तावेज़ की खरीद एवं निविदा/ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

भारत के राष्ट्रपति, ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रणाली एवं आँकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय के प्रधान महानिदेशक के द्वारा सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सी.आई.एस) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आई.ए) के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) Tender Id.: 2025_DREV_889258_1 दिनांक 10.12.2025 के माध्यम से आमंत्रित की गई थी, जिसमें आरईओआई दस्तावेज खरीदने एवं निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21.01.2026 निर्धारित की गई थी।

संबंधी दस्तावेजों खरीदने एवं निविदा / आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21.01.2026 शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से विस्तारित करके 31.01.2026 शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) तक कर दी गई है।

सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। विस्तृत सूचना और भाग लेने के लिए कृपया ई-टेंडर वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर जाएं।

CBC 15502/11/0050/2526

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार) पश्चिम मध्य रेल भोपाल भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिये कार्य करते हुये निम्न कार्यो हेतु ई-निविदा आमंत्रित करते है। इन टेन्डर्स के तहत मैनुअल प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे एवं ऐसे प्राप्त कोई भी मैनुअल प्रसताव को स्वीकार नही किया जायेगा। निविदा से संबंधित दस्तावेज वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड कर दिये गये हैं। **निविदा सूचना एवं क्रमांक** : बीपीएलएनवर्क्स 2025-26 सिगनल 16, **कार्य का नाम** : भोपाल डिवीजन इनक्रीस ऑफ CSR एंड क्रॉसओवर रिवर्सल ऑन बोथ एंडस एट बानापुरा स्टेशन इन ET-KNW सेक्शन इन्वोल्विंग आउटडोर वर्क & इंडोर अल्टरेशन वर्क इन एक्सिस्टिंग EI, **कार्य की अनुमानित लागत** : 1,82,28,885.45, **निविदा फार्म की कीमत (non fundable) :** लागू नहीं, **जमा की जाने वाली बयाना राशी:** 2,41,200.00, **कार्य समापन की अवधी:** 12 माह, **निविदा जमा करने एवं खोलने की दिनांक एवं समय:** दिनांक 09.02.2026 को 15:00 बजे तक दिनांक 09.02.2026 को 15.30 बजे, **निविदा सूचना एवं क्रमांक** : बीपीएल एनवकर्स 2025-26 सिगनल 17, **कार्य का नाम** : BPL DIV : कंडक्टिंग सर्वे & डिजिटिजेशन ऑफ एक्सिस्टिंग अंडरग्राउंड सिग्नल एंड टेलीकम्यूनिकेशन केवल्स विथ RTK (रियल टाइम कयनेमैटिक्स) DGPS (डिफ्रेटिअल GPS) टेक्सोलॉजी यूसिंग GNSS (ग्लोवल नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम) इन्क्लूडिग प्रिपरेशन ऑफ डिजिटलिज्ड सिम्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन प्लान ओवर एटायर भोपाल डिवीजन, **कार्य की अनुमानित लागत:** 7,72,03,826.02, **निविदा फार्म की कीमत (non fundable) :** लागू नही, **जमा की जाने वाली बयाना राशी** : 5,36,000.00, **कार्य समापन की अवधी:** 12 माह, **निविदा जमा करने एवं खोलने की दिनांक एवं समय:** दिनांक 11/02/2026 को 15.00 बजे तक दिनांक 11/02/2026 को 15:30 बजे निविदाकर्ता/विडर्स के पास क्लास III डीजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है एवं IREPS पोर्टल पर पंजीकृत डोना चाहिये। केबल पंजीकृत निविदाकर्ता/विडर्स ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते हैं। ई-टेंडरिंग के दौरान ही सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है पेमेन्ट के द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज की कीमत, बयाना राशि आदि का भुगतान ऑनलाइन मल्टीपल नेटबैकिंग, डेविट एवं क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है।

मण्डल रेल प्रबंधक (सिग्नल एवं दूरसंचार), पमरे, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर